HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 1747/2026
CNR: RJHC021008392026 | URN: CCP / 1833U / 2026

Havildar Ghanshyam Yadav (Retd.) S/o Shri Mali Ram, Aged About 42 Years, R/o Village Nimli, Post Sirohi, Tehsil Neem Ka Thana, District Sikar.

----Petitioner

Versus

1 Shri Ashish Modi, District Collector, Sikar.

2 State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Department Of Home, Secretariat, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Mahesh Kalwania
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE BIPIN GUPTA

Order

17/11/2026

1. The present contempt petition has been filed for non-compliance of the order dated ***09.09.2025*** passed by a Co-ordinate Bench of this Court in ***S.B. Civil Writ Petition No. 13535/2025***. The relevant portion is reproduced as under:-

> *"1. Learned counsel for the petitioner has submitted that instant petition can be disposed of with a liberty to the petitioner to file a representation, within a period of seven days before the competent authority.*
>
> *2. Heard.*
>
> *3. This Court directs Respondent No.4 to consider the representation (Annexure-16)/legal notice dated 31.07.2025 of the petitioner and decide the same within a period of 30days, strictly in accordance with law, expeditiously as per the ratio encapsulated in light of* ***Pawan Meena vs. State of Rajasthan & Ors. (SBCWP No. 1665/2024)*** *and Circular issued by the*

Chief Secretary for the State of Rajasthan, dated 19.02.2024 (No. प.10(1) प्रसु./अनु.–1/2012).

4. In light of the aforestated, the present petition is disposed of with the aforesaid liberty being granted. Pending applications, if any, stand disposed of."

2. Learned counsel for the petitioner submits that the representation of the petitioner has wrongly been rejected by the respondent and therefore, they have committed contempt of Court.

3. This Court finds that after the order dated 09.09.2025 passed by Co-ordinate Bench of this Court, a detailed order has been passed by respondent No.2 on 18.11.2025 which is reproduced as under:-

"यह है कि आप द्वारा दिनांक 11.09.2024 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना के यंहा शस्त्र अनुज्ञापत्र के पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया, जो कि जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल द्वारा जारी किया हुआ था।

आवेदक के सन्दर्भ में जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत् तहसीलदार नीमकाथाना, पुलिस अधीक्षक नीमकाथाना एवं जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल को लिखा गया।

जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना द्वारा जाँच रिपोर्ट हेतु जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल को लिखे पत्र के सन्दर्भ में अति. जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल द्वारा दिनांक 28.12.2024 को रिपोर्ट भेजी गई।

प्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र के पंजीकरण के संबंध में SBCWP No.13535/2025 दायर की गई। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया।

"this Court directs respondent No.4 to consider the representation (Annexure-16)/legal notice dated 31.07.2025 of petitioner and decide the same within a period of 30 days, strictly in accordance with law, expeditiously as per the ratio encapsulated in light of Pawan Meena Vs. State of Rajasthan & Ors. (SBCWP No.1665/2024) and circular issued by the Chief Secratory for the state of Rajasthan, dated 19.02.2024 (No. प. 10 (1) प्रसु/अनु-1/2012).

In light of the aforestated, the persent petition is disposed of with the aforesaid liberty being granted, pending applications, if any, stand disposed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित SBCWP No.1665/2024 में दिनांक 02.02.2024 को न्यायालय ने निम्न आदेश पारित किया।

In this regard, chief Secretary for the state is directed to issue instructions to the state instrumentalities to consider the representation of aggrieved parties and dispose of the same by way of speaking orders, so that frivolous/uncalled for litigation is cut-down before the already exceedingly over-burdened courts.

Resultantly, in the facts and circumstances of the present case, the respondent- State is directed to pay due and timely heed to the representation preferred by the petitioner on 23.08.2023 and thereafter, pass a speaking order within a period of 30 days. It is expected that the principles of natural justice shall be adhered with.

In terms of the directions noted above, the instant petition is disposed of.

उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप.1) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 19.02.2024 को निम्न निर्देश दिए:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा SBCWP No.1665/2024 पवन मीणा बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 के क्रम में सभी प्रशासनिक विभागो को निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयो में प्राप्त अभ्यावेदनों का संवेदनशीलता से विवेचन कर इनका प्रभावी रूप से त्वरित निस्तारण करें। साथ ही अभ्यावेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का परीक्षणोपरान्त गुणावगुण पर समयबद्ध निस्तारण कर स्पष्ट भाषा में स्वयं निहित व समुचित आदेश जारी करें। जिससे संबंधित अभ्यावेदनकर्ता को स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके एवं अनावश्यक वादकरण की स्थिती उत्पन्न ना हो। उपरोक्त आदेश SBCWP No.1665/2024 एवं परिपत्र 19.02.24 के प्रकाश में आपके द्वारा प्रस्तुत Legal Notice/अभ्यावेदन का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.12.2024 अनुसार आपके शस्त्र अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि, 25.12.2020 है। आपके शस्त्र अनुज्ञापत्र के पंजीकरण के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन का गृह (ग्रुप-9) विभाग जयपुर के परिपत्र कंमाक प.1 (3) गृह9/2018 पार्ट-1 दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु संख्या 03 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 17 के सन्दर्भ में विचार किया गया। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 03(4) में शस्त्र अनुज्ञापत्र के पंजीकरण के संबंध में प्रावधान है कि अगर अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त हो हो जाती है एवं अनुज्ञापत्रधारी नवीन स्थान पर निवास करता है जिसकी अधिकारिता मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी / नवीनीकरण प्राधिकारी से भिन्न हो तो प्रथमतः पूर्व नवीनीकरण / पंजीकरण प्राधिकारी से नवीनीकरण करवाने के पश्चात ही नये स्थान पर अनुज्ञापत्र का पंजीकरण करायेगे परन्तु सरकार के पदस्थापित लोकसेवक अपने पदीय कर्तव्य के धारण पर जीवन की जोखिम की वजह से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया हो और ऐसी लोक सेवक का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो वह नवीन पदस्थापन स्थान पर अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराकर पंजीयन करवा सकेगें।

चूंकि अति. जिला मजिस्ट्रेट, गांधरबल की रिपोर्ट अनुसार आपका शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 25.12.2020 तक ही वैध है।

*अतः उक्त प्रावधान के मददेनजर **"पूर्व नवीनीकरण / पंजीकरण प्राधिकारी"** से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करवाने के पश्चात ही नये स्थान (जिला मजिस्ट्रेट, सीकर) पर शस्त्र अनुज्ञापत्र का पंजीकरण किया जा सकता है। तद्नुसार उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।*

संलग्नः उपरोक्तानुसार

4. On perusal of this order, this Court finds that order dated 09.09.2025 passed by learned Single Judge has sufficiently been complied and no contempt is made out.

5. However, if the petitioner is aggrieved by the disposal of his representation as done by respondents vide order dated

18.11.2025, the petitioner would be at liberty to seeks appropriate legal remedy as available to him.

6. Accordingly, the present civil contempt petition is **dismissed** with the aforesaid liberty.

(BIPIN GUPTA),J

Crt_21/D-A/54/MAHIMA